मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- हरिजन एक्ट का दुरूपयोग बिगाड़ रहा सामाजिक तानाबाना। 3
- सांप की रस्सी और रस्सी का सांप बनाने में महिर पुलिस
- बिहार में भाजपा की हार : काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। 4
- हरियाणा की चीनी मिलों की आड़ में लूट का बड़ा स्कैंडल। 5
- इएसआई अस्पताल में श्रमिक की मौत 8
- बीके अस्पताल के डॉक्टरों पर झांसी पुलिस की दबिश

वर्ष 29 अंक 1 फरीदाबाद, सोमवार, 16-30 नवम्बर 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

पुलिस कमिश्नर काटेंगे-एनआईए प्रमुख चाटेंगे

कानून-संविधान हुये एकदम फालतू जब भीमसेन बस्सी और शरद कुमार बने पालतू

मोदी सरकार में राजनाथ सिंह के गृह मंत्रालय ने बहुत जल्दी पुलिस अफ़सरों को पालतू बनाने के नए आयाम स्थापित कर लिए हैं। एक बार टुकड़े पाकर पालतू बन जाने के बाद उनसे मनमाफिक किसी को भी कटवा लो या फिर किसी को भी चटवा लो। देश के दो वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी . दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी और एनआइए के मुखिया शरद कुमार इसके ताजातरीन ज्वलंत उदहारण बन गए हैं। बस्सी ने 'आप' के आधा दर्जन विधायकों को आपराधिक मामलों में उलझा रखा है तो शरद ने हिंदुत्व आतंकी गिरोह के विरुद्ध चल रहे गंभीरतम मुकदमों को भी कमजोर करने का अभियान छेड़ रखा है। पुरस्कार स्वरुप बस्सी को पांच वर्ष के लिए भारत का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा रहा है और शरद का सेवाकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

नई दिल्ली (म.मो. ब्यूरो)

इस हाथ ले उस हाथ दे की कवायद में मोदी-राजनाथ ने बेहिचक अपने पत्ते खोले हैं। ध्यान रहे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के हाथों मिली करारी हार को भाजपाई पचा नहीं पाए हैं। दिल्ली की जनता ने उन्हें महज तीन सीटें देकर नीचा दिखाया। अब वे उसका बदला आप के टिकट पर निर्वाचित सरसठ विधायकों से लेने को आतुर हैं। उधर कमिश्नर बस्सी, जिनका सेवाकाल फरवरी 2016 में समाप्त हो रहा है, को भी अभी सरकारी ताम.झाम का नशा छोड़ना गंवारा नहीं। बस दोनों एक दूसरे के पूरक बन बैठे। बस्सी ने आप विधायकों के घरेलू हिंसा सरकारी कर्मचारियों से कहा.सुनी, खरीद-फ़रोख्त के दीवानी विवाद, जैसे मामले भी खींच-तान कर संगीन अपराध में बदल दिए और सम्बंधित विधायकों को जेल भेजने में तनिक भी देर नहीं लगायी।

'आप' विधायकों का शासन के मामलों में नौसिखिया होना भी बस्सी के काम आया। मसलन केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री साहब अपनी फर्जी कानून की डिग्री को लेकर झूठ पर झूठ बोलते गए और अंत में राज खुलने पर बुरी तरह लपेटे गए। इसी तरह एक और मंत्री जो एनओसी देने के लिए पांच लाख की रिश्वत मांग रहे थे, आसानी से टेप पर पकड़े गए और अब सीबीआइ की जांच के निशाने पर हैं। वे भी लम्बी जेल

भीमसेन बस्सी	शरद कुमार
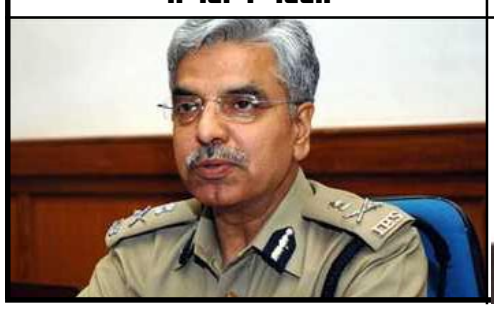	

यात्रा से ज्यादा दूर नहीं हैं। जानकारों का कहना है कि बस्सी ने जंतर.मंतर पर आप की विरोध.सभा के दौरान किसान गजे सिंह की दुर्घटनावश आत्महत्या के मामले में पार्टी के वरिष्ठों मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास को भी टांगने की दिशा में भी जम कर हाथ-पाँव मारे पर बात बनी नहीं। न परिस्थितियां और न ही सबूत उनके काम के सिद्ध हुए।

शरद कुमार ने भी राजनीतिक आकाओं को खुश करने में आतंकी मामलों की केन्द्रीय जाँच एजेंसी एनआइए के दुरुपयोग के आपराधिक झंडे गाड़ने में कोई कसर नहीं रखी। मोदी सरकार और विशेषकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर भाजपा के अधिष्ठता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोर दबाव था कि हिंदुत्व आतंकियों पर चल रहे मुकदमे जल्द से जल्द रफा-दफा किये जाएं। ये मुकदमे हैं, 2007-08 के मालेगांव ब्लास्ट, समझौता कांड, मक्का मस्जिद ब्लास्ट और अजमेर शरीफ काण्ड। इन सभी में हिंदुत्व आतंकी गिरोह की भूमिका रही थी और पूरा गिरोह 2010 तक पुलिस के काबू में आ पाया। उस दौरान भाजपा और संघ के वरिष्ठतम लोगों ने आरोपियों के पक्ष में वक्तव्य दिए थे। 2014 में केंद्र में सरकार बनते ही उन्हें अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का मौका मिल गया।

उपरोक्त सभी मामले अदालतों में होने के कारण शरद कुमार ने गवाहों और अभियोजकों को बरगलाने का रास्ता चुना। गवाहों की गवाही न करवना या उनसे विपरीत बयान दिलवा कर केस को कमजोर करने का सिलसिला जोर-शोर से चलाया जा रहा है। हालाँकि अभियोजकों को दबाने के सिलसिले में शरद एंड कंपनी से एक चूक हो गयी और अब वह मामला उच्च न्यायालय के सामने पहुँच गया है। मुम्बई स्थित एनआइए के आईजी ने अभियोजक पर मालेगांव मामले में दबाव बढाया तो उसने स्वयं को केस से ही अलग कर लिया। फ़िलहाल, अभियोजक की इस सम्बन्ध में एफ़िडेविट पर न्यायालय ने एनआइए और केंद्र सरकार को नोटिस दिया हुआ है। शरद कुमार को 31 अक्तूबर को सेवा निवृत्त होना था पर उससे चंद दिन पहले इस पालतू बन चुके पुलिस अफ़सर का सेवा काल मोदी सरकार ने एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार के अपने नवीनतम नियम के मुताबिक इस तरह की सेवा वृद्धि केवल कैबिनेट सेक्रेटरी को ही दी जा सकती है। पर जब सर्वोच्च स्तर पर नियम.भंग हो तो पूछे कौन।

मानना पड़ेगा कि कमिश्नर बस्सी को बेशर्मी में विशेष ही महारत हासिल होगी। अन्यथा उनके मानकों से तो स्वयं प्रधानमन्त्री मोदी और शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को भी फर्जी शिक्षा डिग्रियां घोषित करने के जुर्म में जवाबदेह बनाया जाना चाहिए था। दोनों ने जिन शिक्षा उपाधियों का दावा अपने.अपने चुनावी दस्तावेजों में किया उससे बाद में किनारा जरूर कर लिया पर इससे उनकी आपराधिकता समाप्त नहीं हो जाती। इसी तरह, तकनीकी नैतिकता के अलमबरदार बस्सी को दिल्ली की विद्युत प्रदाता कम्पनियों के मालिकों अम्बानी और टाटा के विरुद्ध भी जालसाजी और धोखाधड़ी के केस बनाने चाहिए थे। आखिर सीएजी ने इन्हें दिल्ली के उपभोक्ताओं से आठ हजार करोड़ की जालसाजी का दोषी पाया ही है। पर यह करना तो दूर, इस दिशा में सोचने से भी बस्सी का अब तक का सारा पालतूपना व्यर्थ जो चला जाता।

शरद कुमार तो निश्चित ही थूक कर चाटने में बेहद सिद्धहस्त पुलिस अफ़सर होगा। जिस एनआइए ने आतंकी गिरोह का चालान किया हो उसी के अफ़सरों से उन्हीं मुकदमों के गवाहों और अभियोजकों पर दबाव डलवाना कोई साधारण श्रेणी का कारनामा तो नहीं बनता। एक वर्ष की सेवा वृद्धि के लिए आज इस पालतू ने अपना जमीर और विभाग की साख बेची है, कल को कुछ और फ़ायदे के लिए यह देश को भी बेच दे तो क्या ताज्जुब। धिक्कार है कि स्वयं को राष्ट्रवादी कहने वाले मोदी और राजनाथ को जो कानून.व्यवस्था और न्याय.व्यवस्था के मंच पर इन छद्म नाटकों के मुख्य सूत्रधार हैं।

ख़बर दार

गाय की भी सुनो

बिहार चुनाव में गाय पर चर्चा बहुत हुई। सवाल यह भी बनता है कि आखिर गाय की अपनी सोच क्या है? एक ओर उसे माता-माता कह कर वोट बटोरने वाले हैं तो दूसरी ओर गाय की आड़ में अपना सर्वस्व लुट जाने के भय में जी रहे लोग। 'मज़दूर मोर्चा' ने यही ठीक समझा कि बेचारी गाय का हाल-चाल उसी के मुंह से सुन लें। यह इस लिये और भी जरूरी हो गया क्योंकि तथाकथित चाराखोर लालू की बिहार में पुन: धमाकेदार वापसी हो गयी है।

म.मो.-गौ माता क्या वाकई आपकी वजह से ही दादरी में एखलाक की हत्या की गयी थी? लोग ऐसा ही कह रहे हैं।

गौ माता-लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मेरी वजह से ही बिहार का चुनाव भी हारा और जीता गया है। अरे भई मैं एक दूध देने वाली जानवर हूं बेशक मूझे उन्मादियों ने धार्मिक प्रतीक बना रखा हो या चुनाव में वोट देने की मशीन बनाना चाहते हों। मेरा बेचारे एखलाक से क्या लेना-देना जो मैं उसकी जान की दुश्मन बनती?

म.मो.-जिन्हें आप उन्मादी कह रही हो गौ माता, वे तो आपका सारी दुनिया में ढिंढोरा मां कहकर पीटते हैं। लिहाज़ा, उन्हें यह कैसे मंजूर हो सकता है कि लोग आपके परिवार का गोश्त भी खायें-खिलायें?

गौ माता-ये लोग जो मुझे माता कहते हैं, मेरी क्या दुर्गत करते हैं किसी से छिपा नहीं है। दूध उतारने के लिये मुझे हाड़-चूस इंजेक्शन लगाये जाते हैं और मुझसे उम्मीद की जाती है कि सारा दिन मारी-मारी फ़िर कर अपना पेट भरने के बाद मैं वापस खूंटे पर आ जाऊंगी। दूध सूख जाने के बाद तो मूझे पोलीथीन की थैलियों और कूडे के ढेरों का आसरा रह जाता है। कहीं ग़लती से हमने किसी की सब्जी या खेत में मुंह मार दिया तो लाठियों से हमें 'पूजा' जाता है। बूढे हो जाने पर हमें मां कहने वाले ही कसाई के हाथों बेचने में दो मिनट भी नहीं लगाते।

म.मो.-क्या सरकारों ने और खास करके संघी सरकारों ने गौवध के विरुद्ध कड़े से कड़े कानून नहीं बना रखे हैं।

गौ माता-यह तो ठीक है पर गौवध के लिये बेचने को लेकर तो कोई कानून है नहीं। इसकी आड़ में बेचने वाले बेचते हैं, खरीदने वाले खरीदते हैं। कई राज्य ऐसे भी है कि जहां गोवध गैरकानूनी नहीं है। इस लिये सारी कवायद अपनी आंख में धूल झोंकने वाली ही है।

म.मो.-क्या आपको अपने संघी भक्तों से कोई उम्मीद नहीं? अब तो देश में संघियों की ही सरकार है।

गौ माता-सरकार है तभी तो दादरी में एखलाक को मारा गया। मौके ब मौके ये लोग इसी प्रकार औरों को मेरे नाम पर मारते रहेंगे। वरना इस सरकार के आने के बाद देश के बीफ़ निर्यात में इस कदर वृद्धि क्यों हुई होती? जाहिर है इस सरकार ने भी मुझे विदेशी मुद्रा कमाने और वोट बाज़ार में भुनाने के लायक ही समझ रखा है।

म.मो.-फ़िर भी लाखों-करोड़ों हिन्दुओं की भावनायें गाय के साथ जुड़ी हैं। क्या उसके लिये कुछ नहीं किया जा सकता?

गौ माता-किया तो जा सकता है पर एखलाकों को मार कर नहीं। इसके लिये बाकायदा एक गाय-अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी। यह काम मेरे संघी भक्तों के बस का तो है नहीं। जो हर वर्ष लाखों कन्याओं की भ्रूण हत्या करते हों, वे भला गौ-वध खत्म करने पर क्योंकर अपना समय व ऊर्जा लगाने लगे?

म.मो.-कृप्या गाय अर्थव्यवस्था पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें।

गौ माता-अरे भई पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिसकी जितनी उपयोगिता उसका उतना सम्मान होता है। कन्या को भी तो ये हिन्दुत्ववादी इसी लिये मारते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था में उसकी कोई खास उपयोगिता नहीं होती। मेरा वध भी तभी रूकेगा जब मेरा जीवित रहना ज़्यादा उपयोगी हो। क्या मोदी का नीति आयोग ऐसी कोई नीति नहीं बना सकता जिसमें मेरे वध से ज़्यादा मेरा जीवन अधिक लाभकारी हो। प्राचीन समाज में तो ऐसा ही था। यहां तक कि मेरी प्रकृतिक मृत्यु के बाद हड्डियां व चमड़े भी काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया करते थे। आज तो संघी सरकारों की मेहरबानी से उनका रोजगार भी छिन रहा है और मीट कारखानेदारों का मुनाफ़ा मोटा हो रहा है।

म.मो.- कहीं लालू यादव की वापसी से आपका चारा संकट बढ तो नहीं जायेगा?

गौ माता-क्या इस बीच में लालू यादाव ने अपना सबक सीख नहीं लिया होगा? उन्हें भी समझ आ गया होगा कि देश में खाने को और बहुत कुछ है।

मैगी गयी भी आई भी

भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (फ़साई) के सी ई ओ युद्धवीर सिंह मलिक को इस पद पर एक वर्ष भी रखना मोदी सरकार के लिये भारी हो गया। हरियाणा कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी मलिक के कार्यकाल में मैगी पर प्रतिबंध लगा था। मलिक के फ़साई से तबादले के तुरन्त बाद मैगी से प्रतिबंध हटा लिया गया है।

मोदी सरकार की कार्पोरेटपरस्ती का इसी से पता चलता है कि नीति आयोग में पहले केशनी आनंद अरोड़ा को नियुक्त किया जा चुका था। मलिक को वहां भेजने के लिये अरोड़ा की नियुक्ति को निरस्त किया गया। मैगी पर प्रतिबंध के समय कहा गया कि सरकारी प्रयोगशालाओं में उसके नमूने स्वास्य के मानकों पर खरे नहीं पाये गये। अब इन्हीं प्रयोगशालाओं में मैगी के नमूनों को स्वास्थ्य के मानकों पर खरा घोषित कर दिया है।

इस सारी कवायद ने मोदी सरकार के कामकाज के अपारदर्शी तौर-तरीकों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मैगी के नमूनों को तब फ़ेल करना ग़लत था या अब पास करना गलत है? ऐसा इसलिये क्योंकि मोदी सरकार में पारदर्शिता का नितान्त अभाव है। क्या जिस वजह से (सीसा व मोनोसोडियम ग्लुटोमेट की अधिक मात्रा) मैगी पर प्रतिबन्ध लगा था, वह दूर कर ली गयी है? मलिक के तबादले से तो यही लगता है जैसे प्रतिबन्ध हटाने में वही एकमात्र रूकावट रहे हों।

ध्यान रहे कि मैगी की नैया भी मोदी सरकार के उसी मन्त्री जेपी नड्डा के सहारे पार लगी है जो एम्स के भ्रष्ट अधिकारियों व ठेकेदारों के खिवैया बने थे। एम्स मामले में वहां के ईमानदार सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को हटाया गया था और मैगी मामले में फ़साई के सीईओ मलिक को। स्पष्ट है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार से किस तरह की 'लड़ाई' लड़ रही है।